भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

भारी उद्योग विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1199

जिसका उत्तर मंगलवार 28 जुलाई, 2015 को दिया जाना है

तमिलनाडु में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

1199. श्रीमती वी० सत्यबामा:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय के अंतर्गत तमिलनाडु में स्थित विभिन्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) की इकाइयों का ब्यौरा क्या है और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय के अंतर्गत लाभप्रद पीएसयू का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान स्थानीय लोगों को प्रदान किए गए रोजगार के अवसरों सहित तमिलनाडु के हुए लाभों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये पीएसयू पूर्ण रूप से और दक्षतापूर्वक चल रहे हैं और समाज के लिए अपना सामाजिक दायित्व पूरा कर रहे हैं, कोई तंत्र विकसित किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री

(श्री जी. एम. सिद्देश्वर)

(क): भारी उद्योग विभाग के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के चार उद्यमों अर्थात भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल), एन्ड्रू यूल एंड कंपनी लिमिटेड (एवाईसीएल), रिचर्डसन एण्ड क्रुडास कंपनी लिमिटेड (आरएण्डसी) तथा हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड (एचपीएफ) की अपनी इकाइयां तमिलनाडु में स्थित हैं। वर्तमान में, बीएचईएल और एवाईसीएल लाभ अर्जित कर रही हैं, हालांकि, एचपीएफ और आरएण्डसी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के रुग्ण उद्यम हैं।

(ख): मंत्रालय के अधीन लाभ अर्जित करने वाले केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के गत तीन वर्षों के ब्यौरे की सूची संलग्न है।

(ग): केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के इन उद्यमों की तमिलनाडु में अवस्थिति ने करों/शुल्कों के जरिए, रोज़गार, स्थानीय युवाओं को दिए गए प्रशिक्षण, कार्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) आदि के माध्यम से राज्य के आम आर्थिक विकास की दिशा में योगदान दिया है। बहुत सारे स्थानीय लोगों को तमिलनाडु स्थित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के इन उद्यमों द्वारा विभिन्न स्तरों पर प्रवेश दिया गया/नियोजित किया गया है।

(घ) और (ङ): केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के इन उद्यमों में कार्यकुशलता सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार प्रत्येक वित्त वर्ष की शुरूआत में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करती है। समझौता ज्ञापन में वित्तीय और गैर-वित्तीय प्राचलों सहित लक्ष्य तथा मूल्यांकन मानदंड शामिल होते हैं। सीपीएसई के कार्यनिष्पादन का निर्धारण एमओयू लक्ष्यों की तुलना में प्राप्त उपलब्धियों के आधार पर किया जाता है। एमओयू का एक गैर-वित्तीय प्राचल कार्पोरेट सामाजिक दायित्व है। इस प्राचल के अंतर्गत, अलग-अलग क्रियाकलाप जिनसे सामाजिक लाभ होता हो, से संबंधित लक्ष्य एमओयू दस्तावेज़ में नियत किए जाते हैं और सीपीएसई के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन इन लक्ष्यों की तुलना में किया जाता है।

.....2/-

अनुबंध

लाभ अर्जित करने वाले केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के गत तीन वर्षों के लाभ के आंकड़ों की सूचना दर्शाने वाला विवरण।

क्रम.सं.	**सीपीएसई का नाम**	**निवल लाभ/हानि (करोड़ में)**		
		2012-13	**2013-14**	**2014-15 (अनअंकेक्षित)**
1	एन्ड्रू यूल एण्ड कंपनी लिमिटेड	11.35	22.29	15.22
2	हुगली प्रिंटिंग कंपनी लिमिटेड	0.11	0.15	0.17
3	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	9432.00	5014.00	2021.00
4	ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी लिमिटेड	56.03	16.96	40.00
5	भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड	0.46	4.52	3.75
6	ब्रेथवेट बर्न एंड जेसफ कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड	58.37	68.42	24.27
7	सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	8.11	16.20	8.24
8	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड	31.65	26.11	29.96
9	एचएमटी (इंटरनेशनल) कंपनी लिमिटेड	6.85	0.50	2.64
10	हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड	0.74	0.11	0.49
11	साम्भर साल्ट्स लिमिटेड	0.30	0.44	0.84
12	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड	-6.00	13.60	8.41
13	राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड	39.29	19.88	6.86
	योग	**9639.26**	**5203.18**	**2161.85**

******